बरुण मित्रा भा.प्र.से.
Barun Mitra, IAS

सचिव
न्याय विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
SECRETARY
DEPARTMENT OF JUSTICE
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
GOVERNMENT OF INDIA

अर्ध शासकीय पत्रांक 15011/35/2021-न्याय (एयू) **दिनांक: 15 मार्च, 2021**

मैं आपको न्याय विभाग से संबंधित फरवरी, 2021 माह की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराना चाहूंगा।

1. उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:

मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिनांक 12.02 2021 की अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया गया था।

2. स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति:

चार (04) अपर न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में दिनांक 22 02.2021 की अधिसूचना के माध्यम से स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

3. उच्च न्यायालयों में नए स्थायी न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति:

दिनांक 22.02.2021 की अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली और केरल उच्च न्यायालयों में क्रमश: दो (02) नए स्थायी न्यायाधीश और चार (04) अपर न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

4. अपर न्यायाधीश के कार्यकाल का विस्तार:

श्रीमती न्यायमूर्ति पुष्पा वीरेंद्र गनेडीवाला, बॉम्बे उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश का कार्यकाल दिनांक 12.02 2021 की अधिसूचना द्वारा दिनांक 13.02.2021 से एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

5. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना:

इस महीने के दौरान न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 6.37 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

स्थानीय अदालत की बुनियादी ढांचे की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलेपन की अनुमति देने के लिए तंत्र को सरल बनाने हेतु न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सीएसएस के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश 28 जनवरी, 2021 को जारी किए गये।

6. ग्राम न्यायालय:

ग्राम न्यायालय योजना की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया और मासिक आधार पर डेटा अपलोड करने के लिए यूआरएल, लॉगिन आईडी और पासवर्ड राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया। यह पोर्टल 12 राज्यों में चालू ग्राम न्यायालयों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र, केस निपटान सांख्यिकी और अन्य प्रासंगिक डेटा सहित डेटा की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है।

7. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट:

इस माह के दौरान विभिन्न राज्यों को केंद्रीय हिस्सेदारी (निर्भया फंड) के रूप में 45.26 करोड़ रुपये जारी किए गए। 616 एफटीएससी (330 विशिष्ट पोक्सो अदालतों सहित) कार्यात्मक हो गए हैं । विधि एवं न्याय मंत्री ने एफटीएससी के संचालन में हस्तक्षेप के लिए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों और संबंधित उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ मामला उठाया है।

8. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का चरण II:

वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से, उच्च न्यायालयों ने 24,55,139 सुनवाई कीं और अधीनस्थ न्यायालयों ने 51,83,021 सुनवाई कीं, इस प्रकार 31 जनवरी, 2021 तक कुल 76.38 लाख से अधिक सुनवाई हुईं। कोविड के प्रकोप के बाद से 15 फरवरी, 2021 तक भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 59,309 मामलों की सुनवाई की गई। ।

2992 परिसरों के लक्ष्य में से 2938 न्यायालय परिसरों को वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। बीएसएनएल के साथ मिशन मोड पर काम करके तकनीकी रूप से व्यवहार्य (टीएनएफ) साइटों को नवंबर, 2019 में 58 से घटाकर फरवरी, 2021 में 11 कर दिया गया है। कनेक्टिविटी के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करके इन साइटों से राष्ट्रीय खजाने में 95.45 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई है। इसके अलावा कनेक्टिविटी बाधाओं की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और कनेक्टिविटी दोषों को बहाल करने में लगने वाला समय कम हो गया है।

9. व्यापार करने में आसानी:

मद्रास उच्च न्यायालय ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए एक विशेष पीठ (वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग और वाणिज्यिक प्रभाग) का गठन किया है। दिनांक 06.02.2021 को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नए वाणिज्यिक न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें बेंगलुरु शहर के सभी नौ समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों को समायोजित किया गया है।

निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, प्रि-इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता और निपटान से संबंधित नियमों और प्रपत्रों के सरलीकरण पर गठित समिति ने फीस के युक्तिकरण सहित सरलीकृत वाणिज्यिक न्यायालय नियम, 2021 का पहला मसौदा तैयार किया है।

ई-समन समिति ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ पंजीकृत कंपनियों के ईमेल डेटाबेस का उपभोग करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच विकसित किया है और इसे वाणिज्यिक विवादों में ऑनलाइन समन भेजने की सुविधा के लिए मुंबई और दिल्ली में वाणिज्यिक अदालतों को प्रदान किया है।

समय मानकों और देरी, प्रि-इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता और निपटान और ई-कोर्ट सेवाओं पर सुधार और कार्यान्वयन के तौर-तरीकों का सुझाव देने के लिए लॉ फर्मों के प्रतिनिधियों के साथ तीन उप-समितियां स्थापित की गईं थीं। इन उप-समितियों की सिफारिशें शीघ्रता से प्रस्तुत करने के लिए बैठकें शुरू हो गई हैं।

10. टेली-लॉ:

65,913 व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई, जिसमें 19,668 महिलाएं, 18,248 अनुसूचित जाति, 14,271 अनुसूचित जनजाति और 20,987 अनय पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी शामिल थे। 28 फरवरी, 2021 तक कुल 6,47,193 मामलों में सलाह दी गई। 10 राज्यों में 29 प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 688 वीएलई और 618 पीएलवी ने भाग लिया।

11 न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज):

107 नए वकीलों ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराया, अब तक कुल 2477 वकीलों ने इस कार्यक्रम के तहत पंजीकरण कराया है। न्याय बंधु पैनल कार्यक्रम के तहत कलकत्ता, केरल और पटना उच्च न्यायालयों द्वारा 54 नए प्रो बोनो वकीलों को नामांकित किया गया था। प्रो बोनो क्लब योजना से अब तक 29 लॉ स्कूल जुड़ चुके हैं।

12. पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में न्याय तक पहुंच:

एसएलएसए, जम्मू-कश्मीर द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पचास कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए गए, 08 चयनित कानूनों को शामिल करते हुए माह के दौरान 342 कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 17,860 नागरिकों को लाभ हुआ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश के 10 जिलों में 10 कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित किए।

13. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए):

सभी 24 डीएलएसए द्वारा ई-लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिसमें 133 प्रि-लिटिगेशन मामलों सहित 1945 मामलों का निपटारा किया गया।

मध्य प्रदेश एसएलएसए द्वारा उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय स्तर पर हाइब्रिड मोड के माध्यम से स्थायी और सतत लोक अदालत दिनांक 27.02.21 को अनुसूचित की गई थी जिसमें 2161 मामलों का निपटारा किया गया था

14. ए सी सी निर्देशों का अनुपालन न करना:

शून्य

भवदीय,

हस्ताक्षर/-

(बरुण मित्रा)

श्री राजीव गौबा
कैबिनेट सचिव
कैबिनेट सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली।

प्रति:

माननीय विधि एवं न्याय मंत्री के निजी सचिव, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

(बरुण मित्रा)